



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 48/2017

बउनवान

आनन्दीलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्ममण निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, अटरू जिला बारां
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2- परोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.1.2019

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 11/2016 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 22.3.2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम उम्मेदगंज की सरकारी भूमि किस्म तलाई सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 83 की रकबा 0.96 हेक्टर भूमि पर फसल गेहूँ, सरसो की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 480/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 30.8.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा नहीं है। उक्त विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट भी नहीं है। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.7.2017 को पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 27.7.2017 को आवेदन पेश कर दिनांक 31.7.2017 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोंकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म तलाई पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया और तामील करवाई गयी है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलान्ट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। हम पेरोंकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 22.3.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां